

[2023] 4 एस. सी. आर. 1095

ए.

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एक और

बनाम

अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड और अन्य (2022 की सिविल अपील संख्या 2908)

बी.

अप्रैल 20, 2023

[बी. आर. गवई और विक्रम नाथ, जे. जे.]

बिजली कानून: कानून में परिवर्तन-कोयले का इंटर प्लांट ट्रांसफर-आई. पी. टी., यदि कानून में बदलाव के रूप में योग्य है-प्रत्यर्थी संख्या 1-कंपनी ने बिजली की आपूर्ति के लिए अपीलकर्ताओं-हरियाणा उपयोगिताओं के साथ बिजली परियोजना समझौते किए-प्रत्यर्थी संख्या 1 विद्युत नियामक आयोग-सी. ई. आर. सी. ने नई कोयला वितरण नीति, 2007 में बदलाव के कारण मुआवजे का दावा करते हुए याचिका दायर की-बिजली नियामक आयोग-सी. ई. आर. सी. ने कुछ 'कानून में बदलाव' की घटनाओं के लिए मुआवजे की अनुमति दी-हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड-सी. आई. एल. द्वारा अंतर संयंत्र हस्तांतरण के लिए 19 जून 2013 को जारी किया गया संचार 'कानून में बदलाव' की घटना नहीं होगी; और कानून मुआवजे में परिवर्तन की गणना कोयले की वास्तविक मात्रा-आपूर्ति-स्थिरता-के रूप में की जाएगी: ए. पी. टी. ई. एल. का यह निष्कर्ष कि 19 जून 2013 को अंतर संयंत्र हस्तांतरण की अनुमति देने वाला संचार 'कानून में परिवर्तन' नहीं है, ठीकाऊ नहीं है-उक्त संचार सी. आई. एल. की बैठक में लिए गए निर्णय को संदर्भित करता है जिसमें कोयले के हस्तांतरण की अनुमति केवल खरीदार के स्वामित्व वाले बिजली संयंत्रों या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच दी गई है-संचार सी. आई. एल. के निर्णय को दर्शाता है, जो कानून का एक बल रखने वाला एक सरकारी साधन है-इस प्रकार, आई. पी. टी. के लिए प्रदान किए गए उक्त संचार को रखने में न्यायाधिकरण की गलती 'कानून में परिवर्तन' के बराबर नहीं है, इस प्रकार, ए. पी. टी. ई. एल. के निष्कर्ष को अपास्त करना दिया जाता है-आई. पी. टी. 'कानून में परिवर्तन' के बराबर है-आधार पर 'कानून में परिवर्तन' मुआवजे की अनुमति देना।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

शब्द और वाक्यांश:कानून-इसका अर्थ।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1 "कानून"** की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें सरकारी उपकरणों द्वारा सभी नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं शामिल हैं।[पैरा **24**] [**1103-एच**] ए

एच.

1095

1096 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 4 एस. सी. आर.

1.2 कोयले के इंटरप्लांट हस्तांतरण के संबंध में नए बिजली संयंत्रों के लिए लागू मॉडल एफ. एस. ए. में संशोधन **27** मई **2013** को आयोजित सी. आई. एल. की बैठक में लिए गए निर्णय को संदर्भित करता है। इसके अवलोकन से पता चलता है कि कोयले के हस्तांतरण की अनुमति केवल खरीदार के स्वामित्व वाले बिजली संयंत्रों या इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच ही दी गई है, जिसकी अब तक अनुमति नहीं थी। यह आगे प्रावधान करता है कि खरीदार की संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए कोयले के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी; कि एफ. एस. ए. के तहत सभी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोयले की आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी और मूल बिजली संयंत्र के कारण; कि दोनों बिजली संयंत्रों को नए बिजली संयंत्रों के लिए लागू संशोधित एफ. एस. ए. मॉडल में एफ. एस. ए. निष्पादित करना चाहिए था और कोयला ब्लॉकों से जुड़ी कोई आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। यह आगे प्रावधान करता है कि आई. पी. पी. के मामले में, दोनों संयंत्रों के पास डिस्कॉम के साथ वैध दीर्घकालिक पी. पी. ए. होना चाहिए। किसी भी मामले में लागू एफ. एस. ए. के तहत आपूर्ति की गई मात्रा के साथ किसी संयंत्र को हस्तांतरित की गई मात्रा किसी विशेष वर्ष के लिए अंतरिती संयंत्र के ए. सी. क्यू. से अधिक नहीं होगी जो डिस्कॉम के साथ दीर्घकालिक पी. पी. ए. के समानुपाती है। जिन संयंत्रों को इस व्यवस्था के तहत कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, उन्हें कोयले के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वामित्व में परिवर्तन और संयंत्र की कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं होने की स्थिति में, यह सुविधा वापस ले ली जाएगी। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त संचार सी. आई. एल. के निर्णय को दर्शाता है। सी. आई. एल. भारत सरकार का एक साधन है। इस प्रकार, ए. पी. टी. ई. एल. ने **19** जून **2013** के उक्त संचार को 'कानून में परिवर्तन' के बराबर नहीं रखने में गलती की। [पारस **26,27**] [**1105-बी-एफ**]

बी.

सी.

डी.

ई.

1.3 ए. पी. टी. ई. एल. ने माना कि उक्त संचार सभी सहायक कंपनियों को संबोधित एक प्रशासनिक निर्देश है। ए. पी. टी. ई. एल. इस बात को ध्यान में रखने में विफल रहा कि सी. ई. आर. सी. ने उक्त मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया था, क्योंकि उक्त मुद्दे पर निर्णय ने अन्य दो डिस्कॉम, यानी, एम. एस. ई. डी. सी. एल. और राजस्थान डिस्कॉम को प्रभावित किया होगा। यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि उसी न्यायाधिकरण, तीन महीने के तुरंत बाद, के मामले में

एफ.

जी.

रतन इंडिया पावर लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र विद्युत नियामक

आयोग और एक अन्य ने पूरी तरह से विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। **2022** की सिविल अपील संख्या **5005** और **2022** की **4089** में निर्णय के माध्यम से, महाराष्ट्र विद्युत नियामक ए का समवर्ती दृष्टिकोण

एच.

1097

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड।

आयोग और ए. पी. टी. ई. एल. ने उक्त ई. एफ. सी. को 'कानून में परिवर्तन' माना है। मामले के उस दृष्टिकोण में, ए. पी. टी. ई. एल. का यह निष्कर्ष कि आई. पी. टी. की अनुमति देने वाला **19** जून **2013** का संचार 'कानून में परिवर्तन' नहीं है, टिकाऊ नहीं होगा। [पारस **28-31**] [**1105-एफ**; **1106-डी-ई**; **1107-बी**]

1.4 बोली जमा करते समय, एपी (एम) एल ने एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से मुंद्रा में अपने संयंत्र तक लिंकेज कोयले के परिवहन की लागत को ध्यान में रखा होगा। पी. पी. ए. में दिए गए विवरण के अनुसार, परिवहन का साधन रेलवे के माध्यम से है। इस प्रकार, आई. पी. टी. की अनुमति दिए जाने से पहले, ए. पी. (एम) एल. एम. सी. एल. कोयला खदान, तालचेर से जोड़ने वाले कोयले का उपयोग केवल अपने मूल बिजली संयंत्र, यानी ए. पी. (एम) एल. के उद्देश्य के लिए करने के लिए बाध्य था। केवल आई. पी. टी. के कारण ही वह एम. सी. एल. कोयला खदान, तालचेर से कोयले का उपयोग महाराष्ट्र या राजस्थान में अपने संयंत्र के लिए करने की स्थिति में होगा। इसी तरह, यह अपने अन्य बिजली संयंत्रों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र या राजस्थान में अपने संयंत्र के लिए कोयला संपर्कों का उपयोग

करने का हकदार होगा। इस प्रकार, रेलवे द्वारा परिवहन की लागत में अंतर होना तय है। यदि कोयले को एम. सी. एल. कोयला खदान, तालचेर से ए. पी. (एम) एल. तक पहुँचाया जाना है, तो एम. सी. एल. कोयला खदान, तालचेर से तिरोदा टी. पी. एस. तक रेल परिवहन की लागत की तुलना में रेल परिवहन की लागत अधिक होगी। परिवहन लागत में की गई बचत, यानी एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से 'एक्स' संयंत्र तक कोयले के परिवहन के लिए होने वाली लागत को घटाकर परिवहन की वास्तविक लागत को डिस्कॉम्स को देना होगा, जिसे बदले में अंतिम उपभोक्ताओं को देना होगा। [पैरा **32**] [**1107**-सी-जी]

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

1.5 आई. पी. टी. की अनुमति देने के कारण होने वाले परिवर्तनों से ए. पी. (एम) एल. के साथ-साथ अपीलार्थियों और दो अन्य डिस्कॉम, अर्थात्, एम. एस. ई. डी. सी. एल. और राजस्थान डिस्कॉम प्रभावित होंगे। सी. ई. आर. सी. द्वारा **8** जुलाई **2019** के अपने आदेश में भी इसका अवलोकन किया गया था। उक्त 'कानून में परिवर्तन' के कारण किसी भी पक्ष को क्या लाभ होगा, इस पर काम करने के लिए कोई विशेषज्ञता नहीं है। हालांकि, 'कानून में बदलाव' के कारण रेलवे परिवहन में बचत की लागत पर काम करने और उपयुक्त डिस्कॉम को देने की आवश्यकता है, जिसे आगे उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जा सकता है। सी. ई. आर. सी., जो विशेषज्ञों का एक निकाय है, ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। [पैरा **33**] [**1107**-एच; **1108**-ए-बी]

जी.

एच.

1098 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 4 एस. सी. आर.

ए.

1.6 यद्यपि ए. सी. क्यू.-वास्तविक आपूर्ति के आधार पर 'कानून में परिवर्तन' मुआवजे की अनुमति देने के संबंध में मुद्दे को बरकरार रखा गया है, लेकिन आई. पी. टी. के 'कानून में परिवर्तन' नहीं होने के संबंध में मुद्दे को अपास्त करना दिया गया है। ए. पी. टी. ई. एल. का यह निष्कर्ष कि आई. पी. टी. के लिए **19** जून **2013** का संचार 'कानून में परिवर्तन' के बराबर नहीं है, अपास्त करना दिया गया है। यह माना जाता है कि आई. पी. टी. 'कानून में परिवर्तन' के बराबर है। [पारस **34,35**] [**1108**-सी-डी]

बी.

1.7 एम. एस. ई. डी. सी. एल. के साथ-साथ राजस्थान डिस्कॉम्स को नोटिस देने और अपीलार्थियों और उत्तरदाताओं सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद उक्त 'कानून में बदलाव' के प्रभाव पर काम करने के लिए मामला सी. ई. आर. सी. को भेजा जाता है। हालाँकि, चूंकि उक्त मुद्दा लंबे समय से लंबित है, इसलिए सी. ई. आर. सी. को उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने और निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी पक्ष को प्राप्त होने वाले लाभों की गणना करने का निर्देश दिया जाता है। [पारस **36,37**] [**1108-ई-एफ**]

सी.

एनर्जी वॉचडॉग बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य (2017) 14 एस. सी. सी. 80; महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और डी.

अन्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 233; महाराष्ट्र राज्य

इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड और अन्य **2021** की सिविल अपील संख्या **6927**; रतन इंडिया पावर लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग और एक अन्य अपील

ई.

2021 की संख्या **118** और **2022** की संख्या **40** दिनांक **22** मार्च **2022**-निर्दिष्ट।

संदर्भित निर्णय

एफ.

(2017) 14 एससीसी 80

संदर्भित किया गया है

पैरा **3**

नई दिल्ली में विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 21.12.2021 के निर्णय और आदेश से 2021 की अपील संख्या 211 में। बलबीर सिंह, ए. एस. जी., वी. गिरि, सी. आर्यमा सुंदरम, निरंजन रेड्डी, एस. बी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्तागण, समीर मलिक, सुश्री निकिता चौकसे, आकाश लांबा, चंद्र प्रकाश, सुश्री फरहा मलिक, मेसर्स डी. एस. के. लीगल, पुखरंभम रमेश कुमार, आनंद के. गणेशन, सुश्री पूर्वा सहगल, शुभम आर्य, निकुंज दयाल, अमल नायर, सुश्री पल्लवी सहगल, सुश्री कृति सोनी, रवि नायर, सुश्री कृतिका खन्ना, सुश्री रितु अपूर्वा, सुश्री शिखा सूद, ए.

जी.

एच.

1099

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड।

सुश्री अंकिता गुप्ता, जफर इनायत, सुश्री रीहा सिंह, सुश्री अनुमेहा स्मिटी, अनुश्री बर्धन, नवीन प्रकाश, सुश्री सुरभी कपूर, महेश अग्रवाल, अमित कपूर, सुश्री पूनम सेनगुप्ता, अर्शित आनंद, सुश्री गीतिका शर्मा, सौनक राजगुरु, सुश्री साक्षी कपूर, ई. सी. अग्रवाल, विश्व मुखर्जी, गिरिक भल्ला, यशस्वी कांत, सुश्री अकीला पालेम रामिरेड्डी, सुश्री जूही सेनगुडुवन, सुश्री पल्लवी शर्मा, निशांत कुमार, वैभव कालरा, सुश्री अनीशा उपाध्याय, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. वर्तमान अपील 21 दिसंबर 2021 को बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद 'एपीटीईएल' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसमें अपीलार्थियों द्वारा दायर 2021 की अपील संख्या 331 में, इस प्रकार केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद 'सीईआरसी' के रूप में संदर्भित) द्वारा याचिका संख्या 269/एमपी/2018 में पारित 8 जुलाई 2019 के आदेश को चुनौती दी गई है। ए. पी. टी. ई. एल. ने कोल इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में, "सी. आई. एल.") द्वारा 19 जून 2013 को जारी किए गए पत्र को "कानून में परिवर्तन" कार्यक्रम नहीं माना है।

सी.

डी.

2. संक्षेप में, वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गत:

प्रत्यर्थी संख्या 1-अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड (जिसे इसके बाद "एपी (एम) एल" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने गुजरात राज्य के मुद्रा में 4620 मेगावाट (चरण I और II-4 x 330 मेगावाट, चरण III-2 x 660 मेगावाट और चरण IV-3 x 660 मेगावाट) क्षमता का एक उत्पादन केंद्र स्थापित किया था। एपी (एम) एल ने उत्पादन केंद्र के चौथे चरण से 1424 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए अपीलार्थियों, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लिमिटेड (इसके बाद "हरियाणा यूटिलिटीज" के रूप में संदर्भित) के साथ 7 अगस्त 2008 को बिजली परियोजना समझौते (इसके बाद "पीपीए" के रूप में संदर्भित) किए थे। 3. सी. ई. आर. सी. ने 6 फरवरी 2017 के

अपने आदेश के माध्यम से याचिका संख्या 156/एम. पी./2014 में ए. पी. (एम.) एल. द्वारा दावा की गई कुछ 'कानून में परिवर्तन' घटनाओं के लिए मुआवजे की अनुमति दी। एपी (एम) एल ने प्रस्तुत किया है कि हरियाणा यूटिलिटीज पहले से ही एपी (एम) एल द्वारा उठाए गए पूरक चालान के संदर्भ में भुगतान कर रही थी। इसके बाद, एनर्जी वॉचडॉग बनाम सेंट्रल के मामले में इस न्यायालय के फैसले के कारण।

ई.

एफ.

जी.

विद्युत नियामक आयोग और अन्य **1**, एपी (एम) एल ने एक और याचिका दायर की

एच.

1 (2017) 14 एससीसी 80

1100

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

ए.

नई कोयला वितरण नीति, 2007 (संक्षेप में, "एन. सी. डी. पी. 2007") में परिवर्तन के कारण मुआवजे का दावा करने वाली याचिका संख्या 97/एम. पी./2017 है। इसके बाद, सी. ई. आर. सी. द्वारा कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए गए। इसके बाद, हरियाणा यूटिलिटीज ने याचिका संख्या 97/एम. पी./2017 में 2018 का आई. ए. संख्या 21 दायर किया, जिसमें कहा गया कि ए. पी. (एम.) एल. द्वारा दावा किया गया मुआवजा गलत था क्योंकि ए. पी. (एम.) एल. ने सी. आई. एल. द्वारा 19 जून 2013 को जारी किए गए संचार के तहत अनुमति प्राप्त अंतर संयंत्र हस्तांतरण (संक्षेप में, "आई. पी. टी.") के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले लाभों को ध्यान में नहीं रखा था।

बी.

4. इसके विपरीत, एपी (एम) एल द्वारा यह दावा किया गया था कि हरियाणा उपयोगिताओं ने आईपीटी के आधार पर मासिक बिलों से एक बड़ी राशि को एकतरफा रूप से संशोधित किया। एपी (एम) एल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि आई. पी. टी. के संबंध में हरियाणा उपयोगिताओं के तर्क को सी. ई. आर. सी. द्वारा 31 मई 2018 के अपने आदेश में पहले ही खारिज कर दिया गया है।

सी.

5. इस पृष्ठभूमि में, एपी (एम) एल ने निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए सीईआरसी के समक्ष याचिका संख्या 269/एमपी/2018 दायर की:

डी.

“(क) इस एल. डी. के निष्कर्षों को स्पष्ट और घोषित करें। याचिका संख्या 97/एम. पी./2017 में आयोग के आदेश के अनुच्छेद 61 और 2018 के आई. ए. संख्या 21 पर आयोग याचिका संख्या 156/एम. पी./2014 में दिनांक 1 के आदेश के तहत अनुमोदित करें और शुल्कों से संबंधित कानूनी मुआवजे में परिवर्तन पर भी लागू होता है। और

ई.

(ख) उत्तरदाताओं को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दें। 895.41 करोड़ (रु। 566.83 घरेलू कोयले की कमी से संबंधित करोड़ + रु। 328.58 करोड़ और शुल्कों से संबंधित करोड़) मासिक बिलों/पूरक चालानों से लागू विलंब भुगतान अधिभार के साथ एकतरफा रूप से काटे जाते हैं।”

एफ.

6. सी. ई. आर. सी. ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए:

“मुद्दा संख्या 1: क्या याचिका अधिनियम की धारा 142 के तहत बनाए रखने योग्य है?

जी.

मुद्दा संख्या 2: क्या याचिका संख्या 97/एम. पी./2017 में दिनांक 31.5.2018 के आदेश के पैरा 61 में आई. पी. टी. कोयले के संबंध में हमारा निष्कर्ष याचिका संख्या 156/एम. पी./2014 में दिनांक 6.2.2017 के आदेश में कानून में परिवर्तन के रूप में अनुमोदित विभिन्न करें और शुल्कों के लिए देय मुआवजे के लिए लागू होता है?

एच.

1101

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

मुद्दा संख्या 3: कोयले के अंतर संयंत्र हस्तांतरण का क्या व्यवहार होना चाहिए, अगर इसे कानून में बदलाव माना जाता है?

मुद्दा संख्या 4: घरेलू कोयले की कमी की गणना करने का आधार क्या होना चाहिए?”

7. जहाँ तक मुद्दा संख्या 1 का संबंध है, सी. ई. आर. सी. ने विवाद को बनाए रखने योग्य माना।

बी.

8. जहाँ तक मुद्दा संख्या 2 का संबंध है, सी. ई. आर. सी. ने कहा कि याचिका संख्या 156/एम. पी./2014 में 6 फरवरी 2017 के अपने आदेश को ध्यान में रखते हुए, 9 जून 2012 के ईंधन आपूर्ति समझौते (संक्षेप में, "एफ. एस. ए".) के तहत अन्य संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति, सभी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए मुद्रा टी. पी. पी. की इकाइयों 7,8 और 9 से हरियाणा उपयोगिताओं को बिजली के उत्पादन और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगी। इसलिए इसने हरियाणा उपयोगिताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह केवल उस कोयले के लिए कर और शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिसकी उसने वास्तव में खपत की है न कि आई. पी. टी. कोयले के लिए।

सी.

9. जहाँ तक निर्गम संख्या 3 का संबंध है, सी. ई. आर. सी. ने कहा कि आई. पी. टी. नीति के तहत ए. पी. (एम) एल. द्वारा कोयले का हस्तांतरण अन्य उत्पादन स्टेशनों को भी प्रभावित करता है जो आई. पी. टी. कोयले की खपत कर रहे हैं और अन्य वितरण कंपनियां जिन्हें आई. पी. टी. कोयले का उपयोग करने वाले उत्पादन स्टेशनों द्वारा भी बिजली की आपूर्ति की जाती है। चूंकि अन्य वितरण कंपनियां सी. ई. आर. सी. के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं थीं, इसलिए उन्हें इस मुद्दे से निपटना उचित नहीं लगा। 10. जहाँ तक मुद्दा संख्या 4 का संबंध है, सी. ई. आर. सी. ने एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए कहा कि कमी की मात्रा की गणना आश्वस्त कोयले की मात्रा (संक्षेप में, "ए. सी. क्यू".) और कोयला कंपनियों द्वारा वास्तव में आपूर्ति की गई मात्रा को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

डी.

ई.

एफ.

11. इससे व्यथित होकर हरियाणा यूटिलिटीज ने ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष अपील दायर की।

12. जहाँ तक मुद्दा संख्या 4 का संबंध है, एपीटीईएल ने अपने 21 दिसंबर 2021 के फैसले और आदेश के माध्यम से, एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि 'कानून में परिवर्तन' मुआवजे की गणना एसीक्यू-वास्तविक आपूर्ति के रूप में की जानी चाहिए। 13. जहाँ तक 19 जून 2013 के 'कानून में परिवर्तन' के संबंध में मुद्दे का संबंध है, एपीटीईएल ने इसे 'कानून में परिवर्तन' नहीं माना। इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपील।

जी.

एच.

1102

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

14. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम आर्य और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी को सुना है।

15. श्री आर्य ने कहा कि पी. पी. ए. में दी गई "कानून" की परिभाषा पर विचार करते हुए, 19 जून 2013 का संचार स्पष्ट रूप से "कानून" शब्द के अंतर्गत आएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, सीईआरसी ने अन्य वितरकों की अनुपस्थिति में उक्त मुद्दे का जवाब देने से इनकार कर दिया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. पी. टी. ई. एल. ने इसे 'कानून में परिवर्तन' कार्यक्रम नहीं ठहराकर घोर गलती की है।

बी.

16. दूसरी ओर, डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि 19 जून 2013 का संचार एक अंतर-विभागीय संचार है और इसे 'कानून में परिवर्तन' नहीं माना जा सकता है।

सी.

17. जब हमने बिजली की अपीलों के इस समूह को सुना, तो सभी पक्षों के बीच यह सहमति हुई कि इस न्यायालय को पहले दीवानी अपील का फैसला करना चाहिए

2021 की संख्या **684** (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और अन्य **2**) ["एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल और अन्य", संक्षेप में] और **2021** की सिविल अपील संख्या **6927** (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम जी. एम. आर. वरोरा एनर्जी लिमिटेड और अन्य) तीन के रूप में

डी.

बैच में सभी अपीलों में शामिल मुद्दों में से सामान्य थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि उन दोनों अपीलों का निर्णय तीन सामान्य मुद्दों पर निर्णय लेकर किया जा सकता है। हालांकि, जहां तक अन्य अपीलों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया कि तीन सामान्य मुद्दों के अलावा, कुछ अतिरिक्त मुद्दे भी शामिल थे और यह सहमति हुई कि उन दो अपीलों पर निर्णय लेने के बाद, इन अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करने के लिए अन्य अपीलों पर सुनवाई की जानी चाहिए।

ई.

एफ.

18. उक्त तीन सामान्य मुद्दे इस प्रकार हैं:

(i) क्या एन. सी. डी. पी. 2013 के कारण 'कानून में परिवर्तन' राहत 'वास्तविक' यानी एन. सी. डी. पी. 2007 के संदर्भ में आश्वस्त मानक कोयले की आवश्यकता के 100% के विपरीत होनी चाहिए या एन. सी. डी. पी. 2013 में ट्रिगर स्तरों तक सीमित होनी चाहिए। आश्वस्त कोयले की मात्रा (ए. सी. क्यू.) का 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 75 प्रतिशत?

जी.

((ii) क्या 'कानून में परिवर्तन' राहत की गणना के लिए, संचालन मापदंडों पर 'वास्तविक' पर विचार किया जाना चाहिए या बोली में प्रस्तुत तकनीकी जानकारी के अनुसार?

2 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 233 ए

एच.

1103

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

((iii) क्या 'कानून में परिवर्तन' राहत मुआवजा 1 अप्रैल 2013 (वित्तीय वर्ष की शुरुआत) या 31 जुलाई 2013 (एन. सी. डी. पी. 2013 की तारीख) से दिया जाना है?

19. एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य (उपरोक्त) के मामले में 3 मार्च 2023 के निर्णय और आदेश के माध्यम से पक्षों के सभी विद्वान अधिवक्तों को व्यापक रूप से सुनने के बाद, इस न्यायालय ने उपरोक्त तीन मुद्दों पर विचार करने के बाद उन दो अपीलों का फैसला किया।

बी.

20. इस न्यायालय द्वारा पहले मुद्दे का उत्तर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि घरेलू कोयले की कमी के लिए 'कानून में परिवर्तन' राहत 'वास्तविक' यानी एन. सी. डी. पी., 2007 के संदर्भ में आश्वासन दी गई मानक कोयले की आवश्यकता के 100% के विपरीत होनी चाहिए। जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्टेशन ताप दर (संक्षेप में "एसएचआर") और सहायक खपत पर विनियमों या वास्तविक नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जो भी कम हो। तीसरे मुद्दे का जवाब यह मानते हुए दिया गया कि एन. सी. डी. पी., 2013 के लिए 'कानून में बदलाव' कार्यक्रम की शुरुआत की तारीख 1 अप्रैल 2013 है।

सी.

21. इस प्रकार, अंक संख्या 4 हमारे निर्णय के दायरे में आता है।

डी.

एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य के मामले में दिनांक 3 मार्च 2023

(उपर्युक्त) इसलिए भी ऊर्जा के मामले में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय द्वारा वॉचडॉग (ऊपर)।

22. जहां तक मुद्दा संख्या 2 और 3 का संबंध है, हम पाते हैं कि उक्त मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और यह इस निर्णय पर निर्भर करेगा कि क्या 19 जून 2013 को आई. पी. टी. के लिए प्रदान किया गया संचार 'कानून में परिवर्तन' के बराबर होगा या नहीं।

ई.

23. पी. पी. ए. के तहत परिभाषित "कानून" की परिभाषा को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

“कानून का अर्थ है, इस समझौते के संबंध में, भारत में लागू बिजली कानूनों और किसी भी कानून, अध्यादेश, विनियमन, अधिसूचना या संहिता; नियम, या भारतीय सरकारी साधन द्वारा उनमें से किसी की कोई व्याख्या और कानून का बल रखने वाले सभी कानून और उनमें से किसी के अनुसार या उसके तहत भारतीय सरकारी साधन द्वारा सभी लागू नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं शामिल होंगी और इसमें उपयुक्त आयोग के सभी नियम, विनियम, निर्णय और आदेश शामिल होंगे।”

एफ.

जी.

24. इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि "कानून" की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें सरकारी उपकरणों द्वारा सभी नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं शामिल हैं।

एच.

1104

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

25. 19 जून 2013 के संचार का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

“उप:”कोयले के अंतःस्थापन हस्तांतरण” के संबंध में नए बिजली संयंत्रों के लिए लागू मॉडल एफ. एस. ए. में संशोधन

नए बिजली संयंत्रों (पीएसयू/सरकारी दोनों के लिए) के लिए लागू संशोधित एफएसए के तहत एक बिजली संयंत्र से दूसरे में कोयले के अंतर-बिजली संयंत्र हस्तांतरण की अनुमति देने का प्रस्ताव। पी. यू. और निजी पी. यू.) को 298 वीं सी. आई. एल. बोर्ड की 27.5.13 पर आयोजित बैठक में रखा गया था।

बी.

सी. आई. एल. बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन इस तरह के वितरण की अनुमति दी जो कानूनी जांच के बाद नीचे दी गई हैं।

सी.

क) कोयले के हस्तांतरण की अनुमति केवल खरीदार या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाले बिजली संयंत्रों के बीच ही दी जाएगी। खरीदार की संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए कोयले के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। एफ. एस. ए. के तहत सभी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोयले की आपूर्ति मूल बिजली संयंत्र के कारण अपरिवर्तित रहेगी।

डी.

ख) दोनों बिजली संयंत्रों को नए बिजली संयंत्रों के लिए लागू संशोधित एफ. एस. ए. मॉडल में एफ. एस. ए. निष्पादित करना चाहिए था और कोयला ब्लॉकों से जुड़ी कोई आपूर्ति नहीं होनी चाहिए थी। आई. पी. पी. के मामले में दोनों संयंत्रों के पास डिस्कॉम के साथ वैध दीर्घकालिक पी. पी. ए. होना चाहिए।

ई.

ग) किसी भी मामले में लागू एफ. एस. ए. के तहत आपूर्ति की गई मात्रा के साथ किसी संयंत्र को हस्तांतरित की गई मात्रा किसी विशेष वर्ष के लिए अंतरिती संयंत्र के ए. सी. क्यू. से अधिक नहीं होगी जो डिस्कॉम के साथ दीर्घकालिक पी. पी. ए. के समानुपाती है।

एफ.

घ) उन संयंत्रों को कोयले के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें इस व्यवस्था के तहत कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं।

जी.

ई) स्वामित्व में परिवर्तन और संयंत्र की कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं होने की स्थिति में यह सुविधा वापस ले ली जाएगी, और

च) इस व्यवस्था के तहत जुर्माना/प्रोत्साहन पर उपरोक्त (क) के संदर्भ में विचार किया जाएगा।

एच.

1105

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

नए बिजली संयंत्रों (पीएसयू/सरकार दोनों के लिए) के लिए लागू एफएसए मॉडल में संशोधन को दर्शाने वाला एक बयान। पी. यू. और निजी पी. यू.) संलग्न हैं।”

26. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त संचार 27 मई 2013 को आयोजित सीआईएल की बैठक में लिए गए निर्णय को संदर्भित करता है। इसके अवलोकन से पता चलता है कि कोयले के हस्तांतरण की अनुमति केवल खरीदार के स्वामित्व वाले बिजली संयंत्रों या इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच ही दी गई है, जिसकी अब तक अनुमति नहीं थी। यह आगे प्रावधान करता है कि खरीदार की संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए कोयले के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आगे प्रावधान करता है कि एफ. एस. ए. के तहत सभी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोयले की आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी और मूल बिजली संयंत्र के कारण। यह आगे प्रावधान करता है कि दोनों बिजली संयंत्रों को नए बिजली संयंत्रों के लिए लागू संशोधित एफ. एस. ए. मॉडल में एफ. एस. ए. निष्पादित करना चाहिए था और कोयला ब्लॉकों से जुड़ी कोई आपूर्ति नहीं होनी चाहिए थी। यह आगे प्रावधान करता है कि आई. पी. पी. के मामले में, दोनों संयंत्रों के पास डिस्कॉम के साथ वैध दीर्घकालिक पी. पी. ए. होना चाहिए। यह आगे प्रावधान करता है कि किसी भी मामले में लागू एफ. एस. ए. के तहत आपूर्ति की गई मात्रा के साथ एक संयंत्र को हस्तांतरित की गई मात्रा किसी विशेष वर्ष के लिए अंतरिती संयंत्र के ए. सी. यू. से अधिक नहीं होगी जो डिस्कॉम के साथ दीर्घकालिक पी. पी. ए. के समानुपाती है। यह आगे प्रावधान करता है कि उन संयंत्रों को कोयले के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें इस व्यवस्था के तहत कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। यह आगे प्रावधान करता है कि स्वामित्व में परिवर्तन और संयंत्र की कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं होने की स्थिति में, इस सुविधा को वापस ले लिया जाएगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

27. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त संचार सी. आई. एल. के निर्णय को दर्शाता है। सी. आई. एल. भारत सरकार का एक साधन है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि ए. पी. टी. ई. एल. ने 19 जून 2013 के उक्त संचार को 'कानून में परिवर्तन' के बराबर नहीं रखने में गलती की।

28. ए. पी. टी. ई. एल. ने माना है कि उक्त संचार सभी सहायक कंपनियों को संबोधित एक प्रशासनिक निर्देश है। ए. पी. टी. ई. एल. के निम्नलिखित निष्कर्षों का उल्लेख करना उचित होगा:

एफ.

“109. इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि सी. आई. एल. द्वारा सभी सहायक कंपनियों को संबोधित 298 वीं बोर्ड बैठक (आई. डी. 2) में लिए गए निर्णय के बारे में सूचित करने वाला आई. डी. 1 का पत्र, जिसमें कोयले के आई. पी. टी. की अनुमति दी गई थी, केवल खरीदार या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाले बिजली संयंत्रों और एफ. एस. ए. के तहत सभी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोयले की आपूर्ति के बीच हस्तांतरण (कोयले के) की अनुमति देने के लिए सशर्त था। प्रथम प्रत्यर्थी के विशेष संदर्भ में, यह निम्नानुसार है -

जी.

एच.

1106

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

अगर मुंद्रा टी. पी. एस. एम. सी. एल. कोयला खदान, तालचेर से तारोडा टी. पी. एस. (दोनों अडानी समूह के स्वामित्व वाले) को तारोडा टी. पी. एस. में इस तरह के कोयले के उपयोग के लिए जोड़ने वाले कोयले के अपने हिस्से को स्थानांतरित करता है और भले ही एम. सी. एल. कोयला खदान से जोड़ने वाले कोयले, मुंद्रा टी. पी. एस. के तालचेर (एफ. एस. ए. के संदर्भ में मूल बिजली संयंत्र) का उपयोग वास्तव में तारोडा टी. पी. एस. (हस्तांतरण संयंत्र) में किया गया था, तो कोयले का आई. पी. टी. स्वीकार्य होगा जैसे कि इसका उपयोग मुंद्रा टी. पी. एस. में किया गया था। सरल शब्दों में कहें तो कोयले के आई. पी. टी. का प्रभाव यह है कि आई. पी. टी. कोयले की लागत (लिंगेज घरेलू कोयला) मुंद्रा टी. पी. एस. (आई. पी. टी. योजना के तहत एफ. एस. ए./हस्तांतरणकर्ता संयंत्र के संदर्भ में मूल बिजली संयंत्र) के खाते में बुक की जाती रहेगी और वैकल्पिक कोयले की लागत (लिंगेज कोयले के अभाव में उपयोग किया जाने वाला आयातित कोयला या बाजार आधारित ई-नीलामी कोयला) तिरोदा टी. पी. एस. (आई. पी. टी. योजना के तहत हस्तांतरणकर्ता संयंत्र) के खातों में 'एट्रिब्यूटेड कॉस्ट' के आधार पर बुक की जाती रहेगी।”

बी.

सी.

29. हम पाते हैं कि ए. पी. टी. ई. एल. इस बात को ध्यान में रखने में विफल रहा है कि सी. ई. आर. सी. ने उक्त मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया था, क्योंकि उक्त मुद्दे पर निर्णय ने अन्य दो डिस्कॉम, यानी, एम. एस. ई. डी. सी. एल. और राजस्थान डिस्कॉम को प्रभावित किया होगा। यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि रतन के मामले में तीन महीने के तुरंत बाद वही न्यायाधिकरण डी.

इंडिया पावर लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र विद्युत नियामक

आयोग और अन्य 3 ने पूरी तरह से विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। उक्त मामले में, एम. एस. ई. डी. सी. एल. की ओर से यह तर्क देने की मांग की गई थी कि सी. आई. एल. द्वारा 19 दिसंबर 2017 के अपने परिपत्र के माध्यम से लगाया गया निकासी सुविधा शुल्क (संक्षेप में, "ई. एफ. सी.") 'कानून में परिवर्तन' का गठन नहीं करता है। निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करना उचित होगा:

ई.

"9. यह तर्क देना गलत है कि जैसा कि पहले उद्धृत किया गया है, ऐसे संविदात्मक खंडों के तहत कानूनी घटना में परिवर्तन के रूप में शामिल होने के लिए, जिस साधन से कानून में परिवर्तन होने का दावा किया जाता है, वह कानून के बल के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया होना चाहिए। एनर्जी वॉचडॉग एंड ओआरएस. (ऊपर) में, दृष्टान्त के लिए, भारत सरकार में बिजली मंत्रालय के एक पत्र को भी "कानून की शक्ति" वाले उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी तरह, कुसुम इंगोत्स एंड अलॉयज बनाम भारत संघ (2004) 6 एस. सी. सी. 254 में बिना किसी वैधानिक समर्थन के कार्यकारी निर्देशों को भी "कानून" माना गया था। यह कि कोल इंडिया सरकारी साधन है और इसके द्वारा जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि में संविधान के विनियमन 77 (3) के तहत कानून की शक्ति है।

एफ.

जी.

3 अपील संख्या **2021** की **118** और **2022** की **40** दिनांक **22** मार्च **2022** ए

एच.

1107

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम अदानी पावर (मुद्रा) लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

जी. एम. आर. कमलंगा एनर्जी लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायाधिकरण द्वारा भारत सरकार को स्वीकार कर लिया गया था।"

30. सम तिथि के निर्णय के माध्यम से, 2022 की सिविल अपील संख्या 5005 और 2022 की 4089 में, हमने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में, "एम. ई. आर. सी".) और ए. पी. टी. ई. एल. के समवर्ती दृष्टिकोण को बरकरार रखा है, जिसमें उक्त ई. एफ. सी. को 'कानून में परिवर्तन' माना गया है।

बी.

31. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि ए. पी. टी. ई. एल. का यह निष्कर्ष कि आई. पी. टी. की अनुमति देने वाला 19 जून 2013 का संचार 'कानून में परिवर्तन' नहीं है, टिकाऊ नहीं होगा।

32. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, बोली जमा करते समय, एपी (एम) एल ने एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से मुंद्रा में अपने संयंत्र तक लिंकेज कोयले के परिवहन की लागत को ध्यान में रखा होगा। पी. पी. ए. में दिए गए विवरण के अनुसार, परिवहन का साधन रेलवे के माध्यम से है। इस प्रकार, आई. पी. टी. की अनुमति दिए जाने से पहले, ए. पी. (एम) एल. एम. सी. एल. कोयला खदान, तालचेर से जोड़ने वाले कोयले का उपयोग केवल अपने मूल बिजली संयंत्र, यानी ए. पी. (एम) एल. के उद्देश्य के लिए करने के लिए बाध्य था। केवल आई. पी. टी. के कारण ही वह एम. सी. एल. कोयला खदान, तालचेर से कोयले का उपयोग महाराष्ट्र या राजस्थान में अपने संयंत्र के लिए करने की स्थिति में होगा। इसी तरह, यह अपने अन्य बिजली संयंत्रों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र या राजस्थान में अपने संयंत्र के लिए कोयला संपर्कों का उपयोग करने का हकदार होगा। इस प्रकार, रेलवे द्वारा परिवहन की लागत में अंतर होना तय है। दृष्टान्त के लिए, यदि कोयले को एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से एपी (एम) एल तक पहुँचाया जाना है, तो रेल परिवहन की लागत एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से तिरोदा टीपीएस तक रेल परिवहन की लागत की तुलना में अधिक होगी। हम इस दृष्टान्त को केवल एक दृष्टान्त के रूप में दे रहे हैं। हम पाते हैं कि परिवहन की लागत में की गई बचत, यानी एम. सी. एल. कोयला खदान, तालचेर से 'एक्स' संयंत्र तक कोयले के परिवहन के लिए होने वाली लागत को घटाकर परिवहन की वास्तविक लागत को डिस्कॉम्स को देना पड़ता है, जिसे बदले में अंतिम उपभोक्ताओं को देना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से एपी (एम) एल तक प्रति टन परिवहन की लागत Rs.100 है-और एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से तिरोदा टीपीएस तक Rs.50-प्रति टन है, तो Rs.50-प्रति टन का लाभ देना होगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

33. हालाँकि, हम पाते हैं कि आई. पी. टी. की अनुमति देने के कारण होने वाले परिवर्तनों से ए. पी. (एम) एल. के साथ-साथ अपीलार्थियों और दो अन्य डिस्कॉम, अर्थात्, एम. एस. ई. डी. सी. एल. और राजस्थान डिस्कॉम प्रभावित होंगे। सी. ई. आर. सी. द्वारा 8 जुलाई 2019 के अपने आदेश में भी इसका अवलोकन किया गया था। हम नहीं करते।

एच.

1108

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

उक्त 'कानून में परिवर्तन' के कारण किसी भी पक्ष को क्या लाभ होगा, इस पर काम करने के लिए कोई विशेषज्ञता रखें। हालाँकि, हमारा विचार है कि उपरोक्त पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के आलोक में 'कानून में बदलाव' के कारण रेलवे परिवहन में बचत की लागत पर काम करने और उपयुक्त डिस्कॉम को पारित करने की आवश्यकता है, जिसे आगे उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जा सकता है। सी. ई. आर. सी., जो विशेषज्ञों का एक निकाय है, ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त है। 34. इसलिए हम पाते हैं कि वर्तमान अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। यद्यपि ए. सी. क्यू.-वास्तविक आपूर्ति के आधार पर 'कानून में परिवर्तन' मुआवजे की अनुमति देने के संबंध में मुद्दा बरकरार रखा जाना चाहिए, लेकिन आई. पी. टी. के 'कानून में परिवर्तन' नहीं होने के संबंध में मुद्दा अपास्त करना जाना चाहिए।

बी.

सी.

35. परिणामस्वरूप, हम आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हैं और निम्नलिखित को पारित करते हैं -

आदेश:

(i) ए. पी. टी. ई. एल. का यह निष्कर्ष कि आई. पी. टी. के लिए 19 जून 2013 का संचार 'कानून में परिवर्तन' के बराबर नहीं है, खारिज कर दिया गया है।

डी.

((ii) हम मानते हैं कि आई. पी. टी. 'कानून में परिवर्तन' के बराबर है।

36. पैराग्राफ 32 और 33 में की गई हमारी टिप्पणियों के आलोक में, एम. एस. ई. डी. सी. एल. के साथ-साथ राजस्थान डिस्कॉम्स को नोटिस देने और अपीलार्थियों और उत्तरदाताओं

सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद उपरोक्त 'कानून में परिवर्तन' के प्रभाव पर काम करने के लिए मामला सी. ई. आर. सी. को भेजा जाता है।

ई.

37. हालाँकि, चूंकि उक्त मुद्दा लंबे समय से लंबित है, इसलिए हम सी. ई. आर. सी. को उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने और आज से छह महीने की अवधि के भीतर किसी भी पक्ष को प्राप्त होने वाले लाभों की गणना करने का निर्देश देते हैं।

एफ.

38. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा। कोई लागत नहीं।

निधि जैन

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

जी.

(सहायक: राखी, एलसीआरए)

एच.